SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कुसुम कांति कुजूर, पी–एचडी, **संगीता सक्सेना,** पी–एचडी
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
कुसुम कांति कुजूर, पी–एचडी
संगीता सक्सेना, पी–एचडी
E-mail : kusummam24@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 05/12/2025
Revised on : 06/02/2026
Accepted on : 15/02/2026
Overall Similarity : 00% on 07/02/2026

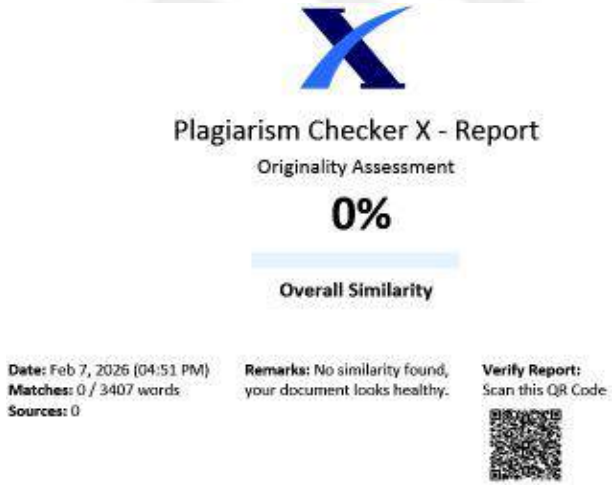

शोध सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में एक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा से जोड़ना एक प्रमुख पहल के रूप में उभरता है। पारंपरिक रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच एक स्पष्ट विभाजन रहा है, जिसके कारण कौशल–आधारित शिक्षा को सामाजिक मान्यता और पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए। इस संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन की अवधारणा, आवश्यकता और व्यवहारिक पक्षों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें नीति दस्तावेजों, शैक्षिक रिपोर्टों तथा द्वितीयक स्रोतों का गहन अध्ययन किया गया है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, इंटर्नशिप, स्थानीय कौशलों का समावेशन तथा उद्योग–शिक्षा सहयोग जैसे प्रावधान विद्यार्थियों की रोजगारपरकता, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को सशक्त बना सकते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि व्यावसायिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, अधोसंरचना, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता है। निष्कर्षतः, यह शोध प्रतिपादित करता है कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन न केवल शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाता है, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यार्थी, शिक्षा.

भूमिका

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारशिला होती है। भारत जैसे विकासशील देश में विद्यालयी शिक्षा न केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम है, बल्कि मानव संसाधन के निर्माण का प्रमुख साधन भी है।[1] वर्तमान में भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली मुख्यतः अकादमिक उपलब्धियों पर केंद्रित रही है, जहाँ रटंत विद्या, परीक्षा–उन्मुखता और सैद्धांतिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है परिणामस्वरूप, शिक्षा और रोजगार के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। बड़ी संख्या में शिक्षित युवा उपयुक्त कौशलों के अभाव में बेरोजगारी या अल्प–रोजगार का सामना कर रहे हैं।[2] यह स्थिति विद्यालयी स्तर पर कौशल–आधारित और व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

इसी संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट कार्य, पेशे या उद्योग से संबंधित व्यावहारिक कौशल, तकनीकी दक्षता और कार्य–अनुभव प्रदान करती है।[3] इसका उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, उद्यमशीलता और कार्य–दक्षता का विकास करना भी है। परंपरागत रूप से भारत में व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा से कमतर आँका गया है, जिसके कारण यह सामाजिक स्वीकृति और संस्थागत समर्थन से वंचित रही।[4] इस विभाजन ने शिक्षा व्यवस्था को एकांगी बना दिया, जहाँ ज्ञान और कौशल के बीच संतुलन स्थापित नहीं हो सका।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक व्यापक और दूरदर्शी सुधार के रूप में सामने आई है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास करती है। NEP 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन करना है, ताकि शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाया जा सके। नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, इंटर्नशिप, स्थानीय एवं पारंपरिक कौशलों का समावेशन तथा उद्योग और विद्यालय के बीच सहयोग जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नीति शिक्षा को केवल डिग्री–आधारित न रखकर कौशल–आधारित बनाने की दिशा में अग्रसर है।[5]

NEP 2020 की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश के चरण में है, जहाँ युवा आबादी की संख्या अत्यधिक है।[6] यदि इस युवा शक्ति को विद्यालयी स्तर से ही व्यावसायिक कौशलों से सुसज्जित किया जाए, तो यह देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन शिक्षा में व्याप्त अकादमिक–व्यावसायिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक हो सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इस कारण भी है कि नीति में किए गए प्रावधानों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अक्सर अंतर पाया जाता है। विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों, सामाजिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं का विश्लेषण आवश्यक है।[7] अतः यह अध्ययन NEP 2020 के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन की अवधारणा, महत्त्व और संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे नीति–निर्माताओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को दिशा–निर्देश प्राप्त हो सकें।

व्यावसायिक शिक्षाः अवधारणा एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ

व्यावसायिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट कार्य, पेशे या उद्योग से संबंधित व्यावहारिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और कार्य–अनुभव प्रदान करना है। यह शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ हाथ–से–काम (learning by doing) की अवधारणा पर आधारित होती है, जिससे शिक्षार्थी वास्तविक जीवन की कार्य–स्थितियों के लिए तैयार हो सकें।[8]

व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, उत्पादकता, कार्य–दक्षता और उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित करती है। आधुनिक समय में, जब श्रम बाजार की माँगें तीव्र गति से बदल रही हैं, तब केवल अकादमिक डिग्रियाँ पर्याप्त नहीं रह गई हैं। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा ज्ञान और कौशल के संतुलन को स्थापित करने का कार्य करती है।[9]

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विकास

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की जड़ें प्राचीन काल तक देखी जा सकती हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत शिल्प, कृषि, व्यापार और हस्तकला जैसे व्यावहारिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता था, जो समाज की आर्थिक आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था।[10]

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने शिक्षा को मुख्यतः प्रशासनिक आवश्यकताओं और क्लर्क तैयार करने तक सीमित कर दिया, जिससे पारंपरिक कौशल–आधारित शिक्षा हाशिए पर चली गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को पुनः स्थापित करने के प्रयास किए। कोठारी आयोग (1964–66) ने पहली बार औपचारिक रूप से माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुशंसा की थी। इसके पश्चात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया।[11]

हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इसका प्रमुख कारण सामाजिक मानसिकता, संसाधनों की कमी, उद्योग–शिक्षा समन्वय का अभाव तथा अकादमिक शिक्षा को श्रेष्ठ मानने की धारणा रही है।[12] परिणामस्वरूप, व्यावसायिक शिक्षा को "द्वितीय श्रेणी की शिक्षा" के रूप में देखा जाने लगा, जिससे विद्यार्थियों की भागीदारी सीमित रही।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य और सम्मानजनक अंग माना जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में "ड्यूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन" के माध्यम से विद्यालय और उद्योग के बीच सशक्त सहयोग स्थापित किया गया है, जहाँ विद्यार्थी सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं।[13]

दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में अपनाया है, जिससे उनकी कार्यशक्ति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकी है।[14] इन देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि यदि व्यावसायिक शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति, गुणवत्ता–युक्त प्रशिक्षण और प्रभावी नीति समर्थन मिले, तो यह राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

इस प्रकार, भारत में व्यावसायिक शिक्षा के ऐतिहासिक अनुभव और अंतरराष्ट्रीय उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रासंगिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक अनिवार्य कदम भी है।

NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान

नीति के प्रमुख उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक केंद्रीय उद्देश्य शिक्षा और कौशल के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी

को कम करना है। नीति यह स्वीकार करती है कि केवल अकादमिक ज्ञान–आधारित शिक्षा 21वीं सदी की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती।[15] इसी कारण NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा में लाने पर बल देती है।

नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को 2025 तक विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त हो।[16] इसके माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल–आधारित दक्षता, कार्य–संस्कृति और आत्मनिर्भरता का विकास करना नीति का स्पष्ट लक्ष्य है। NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा को "वैकल्पिक" या "द्वितीय श्रेणी" की शिक्षा न मानकर अकादमिक शिक्षा के समकक्ष स्थान प्रदान करती है, जिससे सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

विद्यालयी स्तर पर कौशल शिक्षा के प्रावधान

NEP 2020 विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था से ही जोड़ने का प्रस्ताव रखती है। नीति के अनुसार कक्षा 6 से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया जाएगा, जिसमें इंटर्नशिप, हैंड्स–ऑन ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट–आधारित लर्निंग को विशेष महत्व दिया गया है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर वास्तविक जीवन की कार्य–परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करती है।

नीति यह भी सुझाती है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थानीय और पारंपरिक कौशलों को शामिल किया जाए, जैसेकृकृषि–आधारित कौशल, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, तकनीकी मरम्मत, डिजिटल कौशल आदि। इससे शिक्षा का स्थानीय संदर्भ सुदृढ़ होगा और विद्यार्थी अपने परिवेश से जुड़े रोजगार के अवसरों को समझ सकेंगे।[17]

इसके अतिरिक्त, NEP 2020 लचीले पाठ्यक्रम ढ़ाँचे की बात करती है, जहाँ विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अकादमिक तथा व्यावसायिक विषयों का चयन कर सकें। यह बहुविषयक दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक समावेशी और रुचिकर बनाता है।

उद्योग, स्थानीय समुदाय और स्कूल का संबंध

NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण नवाचार विद्यालय, उद्योग और स्थानीय समुदाय के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। नीति स्पष्ट करती है कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए उद्योगों, स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और सामुदायिक संसाधनों की भागीदारी आवश्यक है।[18]

नीति के अंतर्गत विद्यालयों को स्थानीय उद्योगों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य–अनुभव प्राप्त हो सके। यह सहयोग विद्यार्थियों की रोजगार–योग्यता बढ़ाने के साथ–साथ उद्योगों को भी प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराता है।

स्थानीय समुदाय की भागीदारी से पारंपरिक और क्षेत्रीय कौशलों को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने में भी सहायता मिलती है। इससे व्यावसायिक शिक्षा केवल रोजगार–केंद्रित न रहकर सामाजिक–आर्थिक विकास का माध्यम बन सकती है।[19] समग्र रूप से, NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और भविष्य–उन्मुख बनाने का प्रयास करते हैं। यदि इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो विद्यालयी शिक्षा न केवल ज्ञान का माध्यम बनेगी, बल्कि कौशल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव भी रखेगी।

विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन की आवश्यकता

भारत में शिक्षा के प्रसार के बावजूद बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या बनी हुई है। बड़ी संख्या में युवा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार योग्य नहीं हो पाते, जिसका प्रमुख कारण शिक्षा और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के बीच कौशल अंतर है।[20] विद्यालयी शिक्षा का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान और परीक्षा–केंद्रित अधिगम पर आधारित है, जिससे विद्यार्थियों में व्यावहारिक कौशल, कार्य–अनुभव और पेशेवर दक्षता का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता।

व्यावसायिक शिक्षा का विद्यालयी स्तर पर समावेशन इस कौशल अंतर को कम करने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। यदि विद्यार्थियों को प्रारंभिक अवस्था से ही तकनीकी, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख कौशलों से परिचित कराया जाए, तो वे न केवल उच्च शिक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे, बल्कि वैकल्पिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को भी पहचान सकेंगे।[21] इस प्रकार, व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्या के समाधान में एक संरचनात्मक भूमिका निभा सकती है।

अकादमिक–व्यावसायिक विभाजन की समस्या

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच एक स्पष्ट और गहरा विभाजन देखा जाता रहा है। अकादमिक शिक्षा को सामाजिक रूप से श्रेष्ठ और व्यावसायिक शिक्षा को कम प्रतिष्ठित माना गया है, जिसके कारण विद्यार्थी और अभिभावक कौशल–आधारित पाठ्यक्रमों को अपनाने से हिचकते रहे हैं।[22] यह मानसिकता न केवल शिक्षा के विकल्पों को सीमित करती है, बल्कि समाज में श्रम और कौशल के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है।

विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन इस विभाजन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब व्यावसायिक विषयों को अकादमिक विषयों के समान महत्व दिया जाता है और दोनों को एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचे में प्रस्तुत किया जाता है, तो शिक्षा अधिक समावेशी और संतुलित बनती है।[23] इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है और "अकादमिक श्रेष्ठता" की एकांगी धारणा कमजोर पड़ती है।

21वीं सदी की कार्य–दुनिया की मांगें

21वीं सदी की कार्य–दुनिया तीव्र तकनीकी परिवर्तन, डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण से प्रभावित है। आज के श्रम बाजार में केवल विषयगत ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसके साथ–साथ समस्या–समाधान क्षमता, तकनीकी दक्षता, संचार कौशल, अनुकूलनशीलता और उद्यमशील सोच की भी आवश्यकता है।[24] पारंपरिक विद्यालयी शिक्षा इन बहुआयामी क्षमताओं के विकास में अक्सर असफल रहती है।

व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य–परिस्थितियों से जोड़कर इन क्षमताओं का विकास करने में सहायक होती है। प्रोजेक्ट–आधारित अधिगम, इंटर्नशिप और हाथ–से–काम करने के अनुभव विद्यार्थियों को कार्य–दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, बदलते रोजगार स्वरूप जैसे गिग इकॉनॉमी, स्टार्ट–अप संस्कृति और स्वरोजगार के संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाती है।[25]

इस प्रकार, विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन न केवल वर्तमान सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य की कार्य–दुनिया के लिए सक्षम और कुशल मानव संसाधन के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होता है। यह शिक्षा को केवल ज्ञान–केन्द्रित न रखकर कौशल–आधारित, रोजगारोन्मुख और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उभरता है।

क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ

विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक स्पष्ट और प्रगतिशील दृष्टि प्रस्तुत की है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अनेक संरचनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें सबसे प्रमुख चुनौती अधोसंरचना एवं संसाधनों की कमी है। अधिकांश सरकारी और ग्रामीण विद्यालयों में आवश्यक कार्यशालाएँ, उपकरण, प्रयोगशालाएँ और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए अनिवार्य माने जाते हैं।[26] व्यावसायिक शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित नहीं हो सकतीय इसके लिए वास्तविक कार्य–अनुभव, औजारों का उपयोग और तकनीकी अभ्यास आवश्यक होता है। संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नीति के उद्देश्यों और विद्यालयी वास्तविकताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित और दक्ष शिक्षकों का अभाव भी व्यावसायिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन में एक गंभीर बाधा है। पारंपरिक शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः अकादमिक विषयों पर केंद्रित रहे हैं, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए उद्योग–अनुभव, तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।[27] वर्तमान में ऐसे शिक्षकों की संख्या सीमित है जो विद्यालयी स्तर पर कौशल–आधारित विषयों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। इसके परिणामस्वरूप, कई बार व्यावसायिक शिक्षा को भी सैद्धांतिक रूप में पढ़ाया जाता है, जिससे उसका मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। शिक्षक–प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण के बिना नीति के प्रावधान केवल कागजी रह जाने की आशंका बनी रहती है।

व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में सामाजिक और मानसिक बाधाएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारतीय समाज में आज भी अकादमिक शिक्षा को सफलता का प्रमुख माध्यम माना जाता है, जबकि व्यावसायिक या कौशल–आधारित शिक्षा को अक्सर कम प्रतिष्ठित समझा जाता है।[28] अभिभावक और विद्यार्थी यह मानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा उन छात्रों के लिए है जो अकादमिक रूप से "कमजोर" हैं। यह सामाजिक दृष्टिकोण न केवल विद्यार्थियों की रुचि को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यालयों को भी ऐसे पाठ्यक्रम अपनाने से हतोत्साहित करता है। जब तक समाज में श्रम और कौशल के प्रति सम्मान की भावना विकसित नहीं होती, तब तक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

इसके साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच व्याप्त असमानताएँ भी नीति के समान क्रियान्वयन में बाधक हैं। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों, प्रशिक्षण संस्थानों और तकनीकी संसाधनों की अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धता होती है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के अवसर अधिक सुलभ होते हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विद्यालय अक्सर बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग तंत्र विकसित नहीं हो पाता।[29] यह असमानता शिक्षा में समान अवसर की अवधारणा को कमजोर करती है और क्षेत्रीय विषमताओं को और गहरा कर सकती है।

अतः यह स्पष्ट है कि विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन केवल नीति–निर्माण तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए संसाधन–आधारित निवेश, शिक्षक–प्रशिक्षण, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की समन्वित रणनीति आवश्यक है। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना NEP 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकते।

सुझाव एवं अनुशंसाएँ

विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी समावेशन के लिए केवल नीति–निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सुदृढ़ और व्यावहारिक कार्यान्वयन रणनीति की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति अकादमिक विषयों से भिन्न होती है, जिसके लिए उद्योग–अनुभव, तकनीकी दक्षता और कौशल–आधारित शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। अतः पूर्व–सेवा और सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।[30] इसके साथ ही, उद्योग विशेषज्ञों, कारीगरों और तकनीकी पेशेवरों को अतिथि शिक्षक या संसाधन व्यक्ति के रूप में विद्यालयों से जोड़ा जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य–अनुभव का लाभ मिल सके।

दूसरी महत्वपूर्ण अनुशंसा उद्योग–विद्यालय सहभागिता को संस्थागत रूप प्रदान करने से संबंधित है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है जब विद्यालय और कार्य–दुनिया के बीच एक सक्रिय और सतत संबंध स्थापित हो। NEP 2020 भी इस बात पर बल देती है कि विद्यालयों को स्थानीय उद्योगों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों के साथ सहयोग करना चाहिए।[31] इस प्रकार की सहभागिता से इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट–आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विद्यार्थियों की रोजगार–योग्यता में वृद्धि होगी। साथ ही, उद्योगों को भी प्रशिक्षित और कार्य–तत्पर मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय और पारंपरिक कौशलों को विद्यालयी पाठ्यक्रम में समावेशित करना अत्यंत आवश्यक है। भारत की सामाजिक–आर्थिक संरचना विविधतापूर्ण है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ और पारंपरिक कौशल हैं। यदि विद्यालयी शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों से जुड़ती है, तो शिक्षा अधिक प्रासंगिक और जीवनोपयोगी बन सकती है।[32] कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, स्थानीय तकनीकी सेवाएँ और डिजिटल कौशल जैसे क्षेत्रों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति दी जा सकती है।

अंततः, व्यावसायिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करना आवश्यक है। वर्तमान में कई शैक्षिक योजनाएँ उचित निगरानी के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं इसलिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, पहुँच और प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। डेटा–आधारित मूल्यांकन, विद्यालय–स्तरीय फीडबैक तंत्र और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आंकलन से नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन वर्तमान शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच व्याप्त अंतर, कौशल–अभाव और अकादमिक–व्यावसायिक विभाजन जैसी समस्याएँ इस आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। NEP 2020 ने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।[33]

नीति के दीर्घकालिक प्रभावों की दृष्टि से देखा जाए, तो यदि व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में परिवर्तित कर सकती है। विद्यालयी स्तर पर कौशल विकास से विद्यार्थी केवल रोजगार–प्राप्ति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उद्यमशीलता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होंगे। इससे शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली, बहुविषयक और भविष्य–उन्मुख बन सकेगी साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। यह उन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक और सम्मानजनक मार्ग प्रदान करता है, जो पारंपरिक अकादमिक ढाँचे में स्वयं को अनुकूल नहीं पाते। इस प्रकार, शिक्षा सामाजिक समानता, क्षेत्रीय संतुलन और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि NEP 2020 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यदि नीति के प्रावधानों को संसाधन–समर्थन, सामाजिक स्वीकार्यता और प्रभावी निगरानी के साथ लागू किया जाए, तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और मानव–केंद्रित बनाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. Tilak, J. B. G. (2018) *Education and Development in India: Critical Issues in Public Policy*. Palgrave Macmillan, London.
2. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank Publications, Washington.
3. UNESCO. (2015) *Technical and Vocational Education and Training (TVET) Policy Review*, UNESCO, Paris.
4. UNESCO. (2015) *Technical and Vocational Education and Training (TVET) Policy Review*, UNESCO, Paris.
5. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. New Delhi.
6. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank Publications, Washington.

7. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
8. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
9. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
10. Tilak, J. B. G. (2018) *Education and Development in India: Critical Issues in Public Policy*. Palgrave Macmillan, Singapore.
11. Government of India. (1986) National Policy on Education. Government of India, New Delhi.
12. Agrawal, T. (2013) Vocational education and training programs (VET): An Asian perspective. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(1), 15–26.
13. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
14. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
15. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi.
16. Ibid
17. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
18. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
19. Agrawal, T. (2013) Vocational education and training programs (VET): An Asian perspective. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(1), 15–26.
20. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
21. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
22. Agrawal, T. (2013) Vocational education and training programs (VET): An Asian perspective. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(1), 15–26.
23. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi.
24. OECD. (2018) *The Future of Education and Skills: Education 2030*. OECD Publishing, Paris.
25. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
26. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi.
27. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
28. Agrawal, T. (2013) Vocational education and training programs (VET): An Asian perspective. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(1), 15–26.
29. World Bank. (2019) *Skilling India: No Time to Lose*. World Bank, Washington, DC.
30. UNESCO. (2015) *Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training*. UNESCO, Paris.
31. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi.
32. Tilak, J. B. G. (2018) *Education and Development in India: Critical Issues in Public Policy*. Palgrave Macmillan, Singapore.
33. Ministry of Education, Government of India. (2020) *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi.

****